पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख–पत्र

वर्ष 20, अंक 4/2019

महिलाएं वित्तीय साक्षर होकर आर्थिक रूप से मजबूत बनें

'वित्तीय साक्षरता बढ़ने पर महिलाएं बैंकों के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का आसानी से लाभ उठाकर परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती हैं।'

'कट्स' द्वारा 'वित्तीय साक्षरता पहल के माध्यम से विशेष रूप से महिला उपभोक्ताओं के वित्तीय संरक्षण को बढ़ाना' परियोजना के तहत 20 दिसम्बर, 2019 को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय परिचर्चा में राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त आयुक्त रश्मि गुप्ता ने संभागियों को संबोधित करते हुए यह बात कही।

'कट्स' द्वारा यह परियोजना भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान के दो जिलों, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में संचालित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि आज बहुत सी महिलाएं बैंकों से लेन–देन कर रही हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंकों से जुड़कर भी स्वरोजगार की ओर बढ़ रही हैं। इससे कई परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वित्तीय साक्षरता बढ़ने पर महिलाएं सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकती हैं।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के उप महाप्रबंधक मुकेश कुमार ने बताया कि वित्तीय साक्षरता बढ़ने से आम व्यक्ति बैंकों की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य वित्तीय सेवाओं यथा पोस्ट ऑफिस एवं बीमा कंपनियां आदि की सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने अथवा अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों से ऋण भी ले सकता है।

उन्होंने कहा कि आज के समय में डिजिटल लिटरेसी की अत्यन्त आवश्यकता है। वित्तीय साक्षरता द्वारा उपभोक्ता बैंक द्वारा प्रदत्त डेबिट और क्रेडिट कार्ड, विभिन्न डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन लेन–देन का सुरक्षित और सुगमता से उपयोग कर सकता है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने बताया कि रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2014 में सिटीजन चार्टर जारी किया गया था, जिसमें उपभोक्ताओं को बहुत से अधिकार दिए गए हैं। वित्तीय साक्षरता के बारे में आम लोगों में जागरूकता की कमी है। आज के युग में सभी को वित्तीय साक्षर होकर बैंकों से जुड़ना चाहिए। उन्होंने 'कट्स' की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना, वित्तीय समावेश को सुनिश्चित करना तथा उपभोक्ता संरक्षण को प्रोत्साहन देना है।

कार्यक्रम में 'कट्स' के अमरदीप सिंह ने बताया कि 'कट्स' द्वारा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में किए गए बेसलाइन सर्वे के मुताबिक 89 प्रतिशत लोग क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाओं से नहीं जुड़े हैं। वहीं करीब 99 प्रतिशत लोगों ने कभी NEFT/RTGS जैसी सेवाओं का उपयोग नहीं किया। करीब 93 प्रतिशत लोग बैंकिंग लोकपाल के बारे में अनभिज्ञ हैं, साथ ही 92 प्रतिशत लोग बीमा लोकपाल को नहीं जानते।

कार्यक्रम के दूसरे सत्र में चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने परियोजना के तहत अपने–अपने जिलों में किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया। इस सत्र का संचालन मुनीष पी. कोठारी, पूर्व रीजनल डायरेक्टर, भारतीय रिजर्व बैंक तथा ओ.पी.सोमानी, बैंक ऑफ बड़ौदा, भीलवाड़ा ने किया।

परिचर्चा में भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ की लाभान्वित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के प्रतिनिधि, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एवं मीडिया प्रतिनिधियों सहित 70 प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी रही।

इस अंक में...

- करोड़ों का गेहूं हजम कर गए डीलर 3
- भ्रष्टाचार ने तोड़ी कमर, रोकने की मुहिम शुरू .. 5
- कुटीर व लघु उद्योगों के लिए अलग नीति 7
- अटल भूजल योजना शुरू 9
- ऋण लेकर महिलाएं खोल सकती हैं उद्योग ... 10

जैविक खेती में कम लागत से अधिक उत्पादन संभव - जगदीश पारीक

'जैविक खेती में कम लागत से अधिक उत्पादन संभव है जिससे किसान की आय में वृद्धि हो सकेगी' यह विचार सीकर के प्रगतिशील जैविक किसान पद्मश्री जगदीश पारीक ने 'कट्स' द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं की संख्या को जैविक खेती से कम किया जा सकता है।

कार्यशाला में विशेष अतिथि के रूप में डॉ. वी.एस. यादव, डीन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जोबनेर ने सम्बोधित करते हुए कहा कि संतुलित दृष्टिकोण के साथ आधुनिक तकनीकों को जैविक खेती के साथ समन्वय करके थाली में आने वाले जहर की मात्रा को कम करने की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों के साथ तालमेल स्थापित करने की आवश्कता एवं प्रभावी नीतियों की रूपरेखा तैयार करने पर जोर दिया।

'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि कृषि में रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता उपयोग चिंता का विषय है। रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती खपत स्वास्थ्य खतरों की ओर संकेत करती है। रासायनिक उर्वरकों पर आधारित उत्पाद मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। इसलिए ओर्गेनिक उत्पादन और खपत बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि 'प्रोओर्गेनिक II' परियोजना दस जिलों की 192 ग्राम पंचायतों में विस्तारित की गई है।

कार्यशाला में बताया गया कि विश्व का लगभग कुल 30 प्रतिशत ओर्गेनिक उत्पादन भारत में होता है। विश्व ओर्गेनिक कृषि रिपोर्ट 2018 के अनुसार, विश्व के कुल 2.7 मिलियन ओर्गेनिक उत्पादकों में से 8.35 लाख प्रमाणित जैविक उत्पादक भारत में है। कार्यक्रम अधिकारी राजदीप पारीक ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से परियोजना के तहत अब तक की गतिविधियों पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में 35 मीडिया प्रतिनिधि, परियोजना सहयोगी एवं जैविक खेती पर कार्यरत संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित 45 से अधिक भागीदारों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

सामुदायिक साझेदारी ई-वेस्ट प्रबंधन में सहायक सिद्ध होगी - महापौर

'सामुदायिक साझेदारी को अगर दैनिक जीवन में उतारा जाए तो यह सतत विकास एवं आर्थिक विकास के साथ ई-वेस्ट प्रबन्धन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। हमारे जीवन में शेयरिंग परम्परा शुरू से रही है, अगर हम इसे अपना लेते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग कर सकते हैं, इससे पर्यावरण संरक्षण भी होगा साथ ही साथ जन समुदाय में साझेदारी की भावना भी जागृत होगी।'

उक्त विचार महापौर विष्णु लाटा ने 'कट्स' द्वारा संचालित परियोजना 'ग्रीन एक्शन वीक-2019' के तहत इस वर्ष की थीम 'शेयरिंग कम्यूनिटी' पर आयोजित राज्य स्तरीय परिचर्चा में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। परिचर्चा के दौरान महापौर ने 'ई-वेस्ट बिन' का उद्घाटन भी किया।

कार्यक्रम में विजय सिंघल, चीफ एनवायरमेंट इंजीनियर ने कहा कि भावी पीढ़ी के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं तथा ई-वेस्ट से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करें। मानव जीवन को बचाने के लिए किसी भी प्रकार के वेस्ट को रिसाइकिल करना जरूरी है। ई-वेस्ट को प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से रिसाइकिल करने का प्रावधान है। गैर कानूनी तरीके से रिसाइकिल करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।

परिचर्चा के प्रारंभ में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने बताया कि ई-वेस्ट आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही, इससे मानव स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। ई-वेस्ट के निस्तारण और उचित प्रबंधन की आज बहुत ही अधिक आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि 'कट्स' द्वारा एस.एस.एन.सी. स्वीडन के सहयोग से देश के बारह राज्यों में 'ग्रीन एक्शन वीक' कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस साल के कार्यक्रम का मुख्य ध्येय ई-वेस्ट का बेहतर प्रबंधन करना है।

परिचर्चा के दौरान निमिषा शर्मा ने 'ग्रीन एक्शन वीक' के दौरान की गई गतिविधियों पर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया अभियान के दौरान जयपुर में 50 किचन गार्डन विकसित किए गए, ई- वेस्ट संग्रहण, साझा की दीवार, स्कूल मीटिंग, सामुदायिक बैठकें और नुक्कड़ नाटक जैसे कई कार्यक्रम आयोजित कर आम लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही, जयपुर में पांच स्थानों पर ई.टी.सी.ओ. द्वारा ई- वेस्ट संग्रहण सेंटरों की स्थापना की गई है।

करोड़ों का गेहूं हजम कर गए डीलर और अफसर

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कोटा में रसद विभाग में बड़े घोटाले का खुलासा किया है। यह घपला लगभग वैसा ही है जैसा जोधपुर में आईएएस निर्मला मीणा द्वारा किया गया था। करीब साढ़े छह करोड़ रुपए का 44 हजार 920 क्विंटल गेहूं विभाग के अफसर हजम कर गए।

कागजों में इस गेहूं का उठाव हुआ, कागजों में ही डीलरों तक पहुंचा, लेकिन फिजिकली यह गेहूं न उपभोक्ताओं में बंटा और न दुकानों पर मिला। इसी तरह केरोसिन वितरण में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिली। इस सारे खेल का खुलासा तब हुआ जब एसीबी ने 24 मई 2018 को रसद विभाग पर औचक छापा मारा था। एसीबी ने इस पूरे घोटाले में राशन डीलरों व विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत मानते हुए 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच जारी है। *(दै.भा., 27.12.19)*

आवास योजना में करोड़ों की चपत

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में चयनित सात हजार से भी ज्यादा लोग सरकार को करीब 24 करोड़ रुपए की चपत लगा गए। पहले इन लाभार्थियों ने आवासहीन होने की दुहाई देकर पहली किश्त के रूप में 30 हजार रुपए की राशि सरकार से ले ली। लेकिन मकान नहीं बनाए।

केंद्र ने अधूरे आवासों पर जानकारी मांगी तो ग्रामीण विकास महकमे ने पड़ताल कराई तो इसमें 7882 आवासों में गड़बड़ी उजागर हुई। केंद्र को रिपोर्ट में सरकार ने इसे राशि के दुरुपयोग की श्रेणी में डाल कर यह मान लिया कि अब इन आवासों का पूरा होना संभव नहीं है। यह आवास 2016-17 से 2018-19 के बीच स्वीकृत किए गए थे। *(रा.प., 06.11.19)*

फर्जी पेंशनधारी उठाते रहे पेंशन

राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। राजस्थान पत्रिका ने दौसा जिले के लालसोट में ई-मित्र संचालकों की ओर से दस्तावेज में गड़बड़ी कर पेंशन उठाने का मामला उजागर किया था। इस पर कलेक्टर ने जिले में जांच के आदेश दिए थे। जांच में अकेले लालसोट पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्र में 2500 व शहरी क्षेत्र में 25 पेंशनधारी अपात्र मिले। ये हर महीने करीब 18 लाख रुपए पेंशन उठा रहे थे।

अन्य पंचायतों की जांच अभी चल रही है। पूरे प्रदेश में 51.34 लाख लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, ऐसे में फर्जीवाड़े का यह आंकड़ा कहीं बड़ा हो सकता है। कलेक्टर ने ई-मित्र संचालकों को चिन्हित करने और अपात्रों की पेंशन रोकने के आदेश दिए हैं। पेंशन स्वीकृति के लिए अपनाई जाने वाली ऑनलाइन प्रक्रिया इस फर्जीवाड़े की जड़ बनी। *(रा.प., 12.10.19)*

शौचालय की राशि से साबुन-तेल

भीलवाड़ा शहर को खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) बनाने के लिए लोगों को शौचालय बनाने के लिए राशि दी। नगर परिषद के दावे पर कागजों में एक बार तो शहर को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। लेकिन लोगों ने राशि लेकर भी शौचालय नहीं बनवाए। ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर को मिला ओडीएफ का दर्जा वापिस छिन गया।

शौचालय के लिए मिली राशि को किसी लाभार्थी ने दूध वाले को चुका दी तो किसी ने साबुन-तेल व घर की जरूरत के सामान पर खर्च कर दी। मिशन के तहत पड़ताल में यह सच सामने आया कि शहर के करीब चार हजार लोगों को शौचालय बनाने के लिए प्रथम किश्त के रूप में 4,000 रुपए दिए गए। इनमें से मात्र दो हजार लोगों ने ही शौचालय बनाए। *(रा.प., 11.11.19)*

देश के ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी गरीबी

देश में 2011-12 और 2017-18 के बीच ग्रामीण गरीबी में लगभग 4 परसेंटेज पॉइंट्स की वृद्धि हुई है। जबकि शहरी गरीबी करीब 5 परसेंटेज पॉइंट्स कम हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के आंकड़ों के विश्लेषण से यह बात सामने आई है।

ग्रामीण आबादी की अधिकता को देखते हुए अनुमानित समग्र गरीबी दर 2017-18 में लगभग एक परसेंटेज पॉइंट्स बढ़कर करीब 23 प्रतिशत हो गई है। यानी तीन करोड़ लोग भारत की अधिकाधिक गरीबी रेखा से नीचे आ गए और पिछले आधे दशक में गरीबी की श्रेणी में शामिल हो गए। रिपोर्ट के अनुसार देश के किसी राज्य में गरीबी बढ़ गई तो किसी में घट गई। *(रा.प., 04.12.19)*

अधर में अटकी किसान सम्मान योजना

किसानों की खस्ताहाल को देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना शुरू की है। राजस्थान में कुल 51.81 लाख किसान इस योजना के तहत दर्ज हैं। इनमें से 39.95 लाख किसानों को पहली किस्त मिल चुकी है। दूसरी किस्त में यह संख्या घटकर 34.06 लाख रह गई है। अब तीसरी किस्त में तो यह संख्या महज 11.75 लाख ही रह गई है।

कहा जा रहा है कि अब तीसरी किस्त देने से पहले इनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए पहले तो जमीन का रिकॉर्ड होना ही किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है, वहीं अब योजना से आधार कार्ड को जोड़े जाने की प्रक्रिया भी काफी जटिल है। इससे योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। *(रा.प., 13.10.19)*

सरकारी कर्मचारी बन गए गरीब किसान

प्रदेश में फसली ऋण माफी योजना के तहत 50 हजार रुपए तक की ऋण माफी का लाभ लेने के लिए झूठा शपथ पत्र देकर करीब आठ हजार से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने गरीब किसान बनकर आवेदन कर दिया। जबकि ऋण माफी अधिसूचना में साफ लिखा था कि सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं होंगे।

पहले तो बैंकों ने इनका ऋण माफ भी कर दिया लेकिन आधार मिलान से पोल खुल गई और उनकी कर्जमाफी निरस्त की गई। बैंक कर्मचारी सतर्क नहीं होते तो सरकार को 21 करोड़ 76 लाख रुपए का नुकसान होता। खास बात यह है कि अभी भी कई कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से लिए गए ऋण को वापिस नहीं किया है। अब ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। *(रा.प., 12.11.19)*

प्रदेश के सांसदों ने नहीं लिए गांव गोद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई सांसद आदर्श गांव योजना में सांसदों का रुझान घटता दिख रहा है। वित्तीय वर्ष के आठ महीने बीतने के बाद भी राजस्थान में लोकसभा और राज्यसभा के 35 सांसदों में से 17 सांसदों ने ही गांव गोद लेने की जानकारी दी है।

ग्रामीण विकास विभाग की अधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 25 लोकसभा सांसदों में से अब तक 14 और राज्यसभा के 10 में से केवल 3 सांसदों ने विभिन्न जिलों में ग्राम पंचायतें गोद ली है। पूरे देश की सूरत देखें तो भी नवंबर माह तक केंद्र सरकार के पोर्टल पर लोकसभा के 545 सांसदों में से 173 ने और राज्यसभा के 245 में से 37 सांसदों ने ही गांवों का चयन किया है। *(रा.प., 02.12.19)*

भूमि विकास बैंकों को ले डूबी कर्जमाफी

राज्य सरकार की किसान कर्जमाफी योजना ने प्रदेश के भूमि विकास बैंकों की कमर तोड़कर रख दी। प्रदेश के 36 भूमि विकास बैंकों में से 18 बैंक इतने ज्यादा घाटे में डूब चुके हैं कि बैंक प्रबंधन ने इनकी सभी 67 ब्रांचों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया है। इससे इनमें काम कर रहे ठेका कर्मियों को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है।

भूमि विकास बैंकों में पहले चरण की 472 करोड़ की कर्जमाफी में से 364 करोड़ रुपए सरकार वहन कर रही है जबकि 108 करोड़ रुपए का भार भूमि विकास बैंकों पर लाद दिया गया। योजना के तहत सरकार किसान का पूरा मूलधन और आधा ब्याज माफ कर रही है। शेष 50 प्रतिशत ब्याज व कर्ज समय पर अदा नहीं करने के लिए वसूली जाने वाली 100 प्रतिशत जुर्माना राशि की माफी का बोझ भूमि विकास बैंक उठा रहे हैं। *(दै.भा., 12.11.19)*

किसानों से उड़द खरीद में घपला

सवाईमाधोपुर उपखण्ड मुख्यालय पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति के तत्वावधान में ठेकेदार के द्वारा समर्थन मूल्य पर हुई खरीद में हुए घोटाले की जांच पूरी हो चुकी है। इसमें करीब 2 करोड़ 61 लाख 58 हजार 488 रुपए का राजकोषीय घाटा सामने आया है। जानकारी के अनुसार खरीद अक्टूबर 2018 में शुरू हुई थी।

जांच के दौरान सामने आया कि 962 किसानों के अनुसार 7423.63 क्विंटल उड़द की तुलाई होनी थी, जबकि उनकी 17412.50 क्विंटल उड़द तोली गई और वेयर हाउस में जमा करवा दी गई। इसी प्रकार 145 किसानों के 905.50 क्विंटल उड़द की तुलाई अधिक की गई। इस प्रकार समिति मुख्य कार्यकारी व समिति कार्मिकों के द्वारा 2 करोड़ 61 लाख 58 हजार 488 रुपए का राजकोष का घाटा हुआ है। *(रा.प., 16.10.19)*

राशन दुकानों पर अनदेखी का घुन

राशन दुकानों पर मिलने वाले गेहूं में सचमुच के कीड़े तो हैं ही, अनदेखी का घुन भी बुरी तरह से लगा है। राशन दुकानदार सिर्फ गेहूं तौलकर दे रहे हैं, पात्र-अपात्र से मानो उन्हें कोई सरोकार ही नहीं है। ऐसे में पात्र लोगों को उचित लाभ नहीं मिल रहा है। जयपुर सहित पूरे प्रदेशभर में खाद्य सुरक्षा योजना दम तोड़ती दिख रही है।

योजना के तहत पात्र-अपात्र के सत्यापन में भारी खामियां सामने आ रही हैं। अपात्रों को बाहर करने और पात्र लोगों को राहत देने की सरकार की इच्छा पर उचित मूल्य दुकानदार ही पानी फेर रहे हैं। खाद्य विभाग के आदेश के एक माह बाद भी ज्यादातर जिलों में विभाग को सत्यापन संबंधी जानकारी नहीं भेजी जा रही। *(रा.प., 10.12.19)*

स्वच्छ परियोजना में करोड़ों का घोटाला

जनजाति क्षेत्रों में करवाए जाने वाले विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने उदयपुर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन संचालित स्वच्छ परियोजना संस्थान के कार्यालय सहित संभाग के अलावा अन्य कार्यालयों पर छापा मारा। प्रारंभिक जांच में ही संस्थान की ओर से कराए गए निर्माण कार्य के सामान, फर्नीचर, पोषाहार की खरीद आदि में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। ब्यूरो ने संस्थान के कार्यालय से रिकॉर्ड जब्त कर लिया है।

एसीबी को जांच में ऐसे दस्तावेज भी हाथ लगे हैं जिनसे यहां के कार्मिकों का सरकारी खर्च पर मुंबई और गोवा घूमने का खुलासा हुआ। यह भ्रमण किस उद्देश्य से किया गया इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मामले की जांच जारी है। *(रा.प., 20.12.19)*

राजस्थान में रेलवे का बड़ा घोटाला

प्रदेश में रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। जैसलमेर से सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लाइम स्टोन (चूना पत्थर) पहुंचाने में उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल और राजस्थान स्टेट मिनरल्स लिमिटेड के पांच-पांच अफसरों और माइनिंग कॉन्ट्रेक्टर ने हर साल 60 करोड़ रुपए का घोटाला किया।

छह साल से यह घोटाला होता रहा। यानी 360 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है। छह महीने पहले यह घोटाला रेलवे की जानकारी में आया। रेलवे ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। अभी तक की जांच में घोटाले की पुष्टि भी हो गई है। घोटाला और भी बड़ा हो सकता है। यह घोटाला वे-ब्रिज के सॉफ्टवेयर में गड़बडी कर किया गया है। वे-ब्रिज भार तौलने का सॉफ्टवेयर है। *(दै.भा., 20.12.19)*

डकार गए किसानों की सम्मान निधि

प्रदेश में कर्जमाफी योजना में गलत जानकारी देकर सरकारी कर्मचारियों के लाभ उठाने के मामले के बाद अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी गड़बड़ी सामने आने लगी है। इस योजना में भी सरकारी कर्मचारी और अन्य पदों पर बैठे लोगों ने अपनी जानकारी छिपाते हुए लाभ उठा लिया।

अब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में सैम्पल सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत राज्य में पांच प्रतिशत आवेदनों की जांच की जाएगी। गड़बड़ी पाए जाने पर किसान बने लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। योजना के तहत किसानों को साल में छह हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। *(रा.प., 30.11.19)*

स्विस बैंकों से मिला खातों का ब्योरा

आखिरकार भारत को स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों के खातों की जानकारी की पहली खेप मिल गई है। इसमें समझौते के तहत भारत समेत 63 देशों के 31 लाख खातों की जानकारी दी गई है। वहीं बदले में इन देशों से उसे 24 लाख खातों की जानकारी मिली है।

इसमें भारत के 100 ऐसे खातों की जानकारी भी है, जो 2018 में बंद कर दिए गए थे। ब्योरे में खाताधारकों के नाम, पते, जमा रकम, टैक्स आइडी नम्बर, वित्तीय संस्थानों से जुड़ी सूचनाएं, केपिटल इनकम और लेन-देन की जानकारी है। एक्सपर्टस का कहना है कि सारा काला धन एक ही विदेशी धरती पर नहीं होता। इसमें 2014 से पहले के खातों का ब्योरा नहीं दिया गया है। ऐसे में बड़ी रकम या बड़े खाताधारकों का नाम सामने आने की उम्मीद कम है। *(रा.प. एवं दै.न., 08.10.19)*

बड़ी 'मछलियों' को भी पकड़े एसीबी

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को और मजबूत किया जाएगा। छोटी मछलियों के समान ही बड़ी मछलियां भी हैं। एसीबी अधिकारी सभी पर समान कार्रवाई करें। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन देने की दिशा में भ्रष्टाचार पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एसीबी का भी एक ऐसा नंबर होगा जिस पर लोग भ्रष्टाचार की सूचना दे सकेंगे। इस नंबर पर पद का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति जुटाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सूचना दी जा सकेगी। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। *(रा.प. एवं दै.भा., 21.11.19)*

भ्रष्टाचारियों को विभाग दे रहे संरक्षण

राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों को संरक्षण देने का आदेश दिया है, जबकि विभाग ही इसके उलट काम कर रहे हैं। कार्मिक विभाग सहित तमाम सरकारी विभाग भ्रष्टाचार में फंसे अपने कर्मचारियों को बचाने में जुटे हैं। ये विभाग कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं कर रहे हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो 219 मामलों में कई अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिलने का इंतजार कर रहा है। इनमें से सबसे अधिक 45 मामलें कार्मिक विभाग के पास लम्बित हैं। उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तफ्तीश पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश करने से पहले अभियोजन स्वीकृति संबंधित विभाग से मांगता है। स्वीकृति नहीं मिलने पर ऐसे मामले लटके ही रहते हैं। *(रा.प., 24.12.19)*

प्रॉपर्टी के मामलों में घूसखोरी ज्यादा

इंडिया करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 33 प्रतिशत लोग किसी न किसी तरह से पुलिस को रिश्वत दे चुके। साथ ही सबसे ज्यादा 44 प्रतिशत लोगों ने जमीन संबंधी रजिस्ट्रेशन या राजस्व संबंधी काम कराने में रिश्वत दी है। 23 प्रतिशत लोगों ने बिजली, परिवहन विभाग और टैक्स संबंधी मामलों में घूस दी।

सर्वे में प्रदेश के 596 लोगों से बात की गई। सर्वे में सामने आया कि 78 प्रतिशत लोगों ने किसी न किसी तरीके से अपने काम कराने के लिए रिश्वत दी है। करीब 56 फीसदी लोगों ने एक या दो बार रिश्वत दी है। यह भी सामने आया कि 22 प्रतिशत लोगों ने अपने काम के लिए रिश्वत दी ही नहीं या रिश्वत देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। *(दै.भा., 29.11.19)*

भ्रष्टाचार में राजस्थान पहले नंबर पर

यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि भ्रष्टाचार के पैमाने पर देश के राज्यों में राजस्थान पहले नंबर पर है। ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार दूसरे नंबर पर है। झारखंड और उत्तर प्रदेश क्रमशः तीसरे व चौथे स्थान पर है। केरल में रिश्वतखोरी सबसे कम है।

यह सर्वे अक्टूबर 2018 से नवम्बर 2019 के दौरान 20 राज्यों के 248 जिलों से ली गई 1.9 लाख प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। प्राप्त प्रतिक्रियाओं में से राजस्थान में 78 फीसदी लोगों ने माना कि उन्हें अपने काम को पूरा करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। बिहार में 75 फीसदी लोगों ने माना कि उन्होंने कभी ना कभी रिश्वत दी है। *(रा.प., 03.11.19)*

कालेधन की जानकारी से किया इनकार

वित्त मंत्रालय ने भारतीयों के स्विस बैंकों में मौजूद खातों के बारे में किसी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुई कर संधि में गोपनीयता नीति के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। एक आरटीआई के जवाब में मंत्रालय ने कहा है कि विदेशों से प्राप्त हुए कालेधन के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा सकती है।

(रा.प., 24.12.19)

भ्रष्टाचार ने तोड़ी कमर, रोकने की मुहिम शुरू

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 9 दिसम्बर को भ्रष्टाचार निरोधक दिवस पर कहा है कि अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार से हर वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था को 3.6 ट्रिलियन डॉलर (27 हजार अरब रुपए से अधिक) का नुकसान हो रहा है। रिश्वतखोरी, गबन, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और हेरा-फेरी आदि के रूप में भ्रष्टाचार होता है। यह किसी भी रूप में हो इसकी कीमत हमेशा कमजोर संस्थाओं को चुकानी पड़ती है, जिससे आर्थिक गिरावट, बुनियादी सेवाओं पर असर और रोजगार प्रभावित होता है।

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भ्रष्टाचार से लड़ना एक वैश्विक चिंता और चुनौती है, क्योंकि यह संपन्न और गरीब दोनों देशों में है। इसका सीधा असर गरीब वर्ग पर पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भ्रष्टाचार को सबसे बड़ी बाधा मानता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ड्रग्स एण्ड क्राइम ने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए 'युनाइटेड अंगेस्ट करप्शन' अभियान शुरू किया है। इसे नेताओं और श्रमिक संगठनों को साथ लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया है। *(रा.प., 15.12.19)*

एसीबी की गिरफ्त में आया हर दिन एक भ्रष्टाचारी

सरकारी महकमों में बिना घूस के काम करवाना आमजन के लिए मुश्किल हो रहा है। यह हम नहीं, प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई के आंकड़े बोल रहे हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार इस कदर पनप रहा है कि एसीबी की गिरफ्त में हर रोज एक भ्रष्टाचारी आया है। एसीबी ने सत्यापन के बाद ट्रैप की योजना बनाकर 400 भ्रष्टाचारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी ने इन भ्रष्टाचारियों से करीब 5 करोड़ रुपए की राशि बरामद की है। एक वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें तो राजधानी जयपुर में ही एसीबी ने 80 ट्रैप की कार्रवाई की। एसीबी ने सबसे ज्यादा कार्रवाई जयपुर, जोधपुर, हड़ौती में की है।

जयपुर में आय से अधिक संपत्ति के मामलों में 4 करोड़ रुपए बरामद किए गए। नारकोटिक्स विभाग के सहीराम के ढ़ाई करोड़ रुपए व आयकर विभाग की महिला अधिकारी से 52 लाख रुपए बरामद हुए। जोधपुर में 18 मामलों में 4 लाख 40 हजार 400 रुपए बरामद किए। भनक लगने पर तीन मामलों में ट्रैप नहीं हो सके। एसीबी की रिपोर्ट में आरटीओ, पुलिस विभाग से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। धौलपुर में एसीबी ने पांच कार्रवाई की, जिसमें सबसे ज्यादा पुलिस विभाग के कर्मचारी पकड़े गए। कड़वी हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान चौथे पायदान पर है। खास बात यह भी है कि प्रदेश में जनता से जुड़े महकमों में भ्रष्टाचार के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। *(रा.प., 22.12.19)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
अलवर	संतोष गोस्वामी	सेक्शन इंचार्ज, रीको कार्यालय, अलवर	25,000	*रा.प., 11.10.19*
चित्तौड़गढ़	किशन लाल जटिया	लोठियाना की सरपंच ललिता देवी के पति	15,000	*दै.भा., 11.10.19*
जोधपुर	प्रदीप कुमार	असिस्टेंट डायरेक्टर, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट	1,00,000	*दै.भा., 12.10.19*
जयपुर	सुमन गुर्जर	पार्षद व कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष	1,25,000	*रा.प. एवं दै.भा., 12.10.19*
सिरोही	मोहन लाल देव	जिला रसद अधिकारी, सिरोही	40,000	*दै.भा. एवं रा.प., 18.10.19*
राजसमंद	गोपाल बच्छ	खनिज अभियंता, खनिज विभाग, आमेट, राजसमंद	4,00,000	*रा.प. एवं दै.न., 31.10.19*
उदयपुर	दीवानसिंह देवड़ा	अधिक्षण अभियंता, खान विभाग, उदयपुर	1,50,000	*रा.प. एवं दै.भा., 02.11.19*
जयपुर	बजरंग लाल बुनकर	सहायक प्रबंधक, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन	50,000	*रा.प. एवं दै.भा., 07.11.19*
अजमेर	दीपेन्द्र सिंह शेखावत देवेन्द्र सिंह गुर्जर	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, सरवाड़ कैशियर, नगरपालिका, सरवाड़	20,000	*रा.प., 07.11.19*
भरतपुर	संजय सिंह	कांस्टेबल, सीआइडी जोन दफ्तर, भरतपुर	5,00,000	*रा.प. एवं दै.भा., 14.11.19*
अजमेर	कुलदीप जैन अनिल नामा	वरिष्ठ सहायक, अजमेर विद्युत वितरण निगम स.वाणिज्य लिपिक, अजमेर विद्युत वितरण निगम	44,000	*रा.प. एवं दै.भा., 26.11.19*
सवाईमाधोपुर	मनोज मीणा	मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, सवाईमाधोपुर	20,000	*दै. न. एव दै.भा., 01.12.19*
टोंक	जगदीश प्रसाद	एसडीएम, निवाई स्थित कार्यालय, टोंक	30,000	*दै.भा., 04.12.19*
सीकर	मुक्ता वर्मा सोनी	आरटीओ इंस्पेक्टर, रींगस परिवहन कार्यालय	70,000	*रा.प. एवं दै.न., 05.12.19*
भीलवाड़ा	सहीराम विश्नोई ओम प्रकाश चौधरी	हैड कांस्टेबल, प्रतापनगर थाना, भीलवाड़ा कांस्टेबल, प्रतापनगर थाना, भीलवाड़ा	1,00,000	*दै.भा. एवं रा.प., 16.12.19*
जयपुर	संजय कोठारी जोगेश्वर शर्मा	अधीक्षण अभियंता, राज. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समकक्ष पद पर पदोन्नत अधीनस्थ जेईई	30,000	*रा.प.एवं दै.भा., 20.12.19*
जयपुर	राकेश कुमार राजपूत विष्णु खंडेलवाल ओम प्रकाश कुमावत	निजी सचिव (संविदाकर्मी) सीइओ, जिला परिषद संचालक, राजस्थान ह्यूमन केयर फाउंडेशन दलाल	2,00,000	*रा.प. एवं दै.न., 25.12.19*
कोटा	पन्नालाल मीणा	अधीक्षण अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग	1,00,000	*दै.भा. एवं रा.प., 26.12.19*

तकनीक से किसान बढ़ाएं आमदनी

राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि कृषि में नवाचार करके और आधुनिक तकनीक को अपनाकर किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। जयपुर जिले के जोबनेर में श्रीकर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में किसानों के लिए आयोजित 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए उन्होंने कहा कि खेती के जरिए ही किसान अपने बच्चों को स्वावलंबी बना सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अन्न उत्पादन ही खेती नहीं है। अब खेती के माध्यम से अनेक कुटीर उद्योग और धंधे चलाए जा सकते हैं। जैविक खाद व कीटनाशकों का उत्पादन बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और पशुपालन से किसानों को जोड़ने के तरीके भी कृषि वैज्ञानिकों को बताने होंगे। *(दै.न., 12.11.19)*

आधार से लिंक करानी होगी संपत्ति

अचल संपत्ति के स्वामित्व के लिए अब उसे आधार से लिंक कराना होगा। केंद्र सरकार पहली बार संपत्ति के स्वामित्व के लिए कानून ला रही है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और 5 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी भी बन चुकी है, जो राज्यों से समन्वय करेगी। जमीन से जुड़े मामले राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए केंद्र सरकार मॉडल कानून बनाकर राज्यों को देगा।

नए कानून से संपत्ति की खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा रुकेगा। बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा होगा। जो व्यक्ति अचल संपत्ति आधार से लिंक कराएगा, उसकी संपत्ति पर कब्जा होता है तो उसे छुड़ाना सरकार की जिम्मेदारी होगी या फिर सरकार मुआवजा देगी। आधार से लिंक नहीं कराने पर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी। *(दै.भा., 26.10.19)*

अप्रैल से लागू होगा 'जन आधार कार्ड'

राजस्थान सरकार ने नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए एक नया कार्ड 'जन आधार' लाने की औपचारिक घोषणा की है। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा 'भामाशाह कार्ड' की जगह 'जन आधार कार्ड' जारी करने की प्रकिया शुरू कर दी गई है। इसे अगले तीन महीने में पूरा किए जाने की उम्मीद है। जन आधार कार्ड 10 अंकों का विशिष्ट नंबर वाला होगा। इसका पंजीयन जन आधार पोर्टल या ई-मित्र पर जाकर मुफ्त में कराया जा सकेगा।

अगले साल एक अप्रैल से यही कार्ड मान्य होगा। इसके अस्तित्व में आने के बाद पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा चलाया गया 'भामाशाह कार्ड' बंद हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जुलाई में पेश अपने बजट में राजस्थान जन आधार योजना लाने की बात कही थी। इसमें भी परिवार की महिला को मुखिया बनाया जाएगा।

(न.नु., 16.12.19)

सरकार ला रही है जवाबदेही कानून

राज्य सरकार प्रदेश में जवाबदेही कानून ला रही है। कानून लागू होने के बाद लोगों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान हो सकेगा। इस कानून से अफसरों और कर्मचारियों के मनमाने रवैये पर शिकंजा कसा जा सकेगा। सरकार कानून के तहत प्रदेश में हर पंचायत स्तर पर सूचना और सहयोग केंद्र खोलेगी, जहां शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा।

उदाहरण के लिए बिजली,पानी, सड़क, पेंशन, राशन, जन्म प्रमाण-पत्र जैसी आम लोगों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए खुली सुनवाई होगी। उपखण्ड अधिकारी की अगुवाई में एक कमेटी बनेगी जो समस्याओं की सुनवाई करेगी। जिसमें जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

(दै.न., 30.12.19)

30 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर

नीति आयोग के सीईओ अभिताभ कांत ने कहा कि वर्ष 2004 से 2018 तक 30 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। आज हर भारतीय के पास बैंक खाता, बायोमेट्रिक पहचान कार्ड और मोबाइल फोन है।

उन्होंने कहा भारत को साल 2025 तक एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी। यहां अत्यन्त गरीब जनसंख्या वाले लोगों का दायरा साल 2022 तक 3 फीसदी रहने की उम्मीद है। साल 2025 तक भारत में अत्यन्त गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यह एक हाल ही में आए एक सर्वे में सामने आया है।

कांत ने कहा कि भारत में जनवरी 2014 से सितम्बर 2018 में 40 हजार से अधिक स्टार्टअप्स की वृद्धि देखी गई है। स्टार्टअप्स का बढ़ना एक क्रांति से कम नहीं है। स्टार्टअप्स भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में एक भूमिका निभा सकते हैं।

(रा.प., 06.10.19)

कुटीर व लघु उद्योगों के लिए अलग नीति बनाए सरकार

सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालय से संबद्ध निर्यात संवर्धन संस्था ने सरकार से कुटीर और लघु उद्योग इकाइयों के लिए अलग नीति बनाने का सुझाव देते हुए कहा है कि गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे इस क्षेत्र को राहत दिलाने के लिए सरकारों को प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहिए। एमएसएमई निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन डीएस रावत ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के उल्लेखनीय योगदान के बावजूद यह क्षेत्र अब भी काफी बाधाओं से जूझ रहा है।

उन्होंने कहा छोटी इकाइयों को समय पर पर्याप्त कर्ज नहीं मिलना, ऊंची ब्याज दर, समनांतर आवश्यकताएं, इक्विटी कैपिटल और बीमारू इकाइयों के पुनरुद्धार की ठोस व्यवस्था नहीं होना इस क्षेत्र की बड़ी समस्याओं में है। केंद्र और राज्य सरकारों को एमएसएमई क्षेत्र के सामने खड़ी इन चुनौतियों से प्राथमिकता के आधार पर निपटना चाहिए। *(न.नु.,19.11.19)*

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के लक्ष्य हासिल होने में कोई समस्या नहीं

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (एमएनआरई) सचिव आनंद कुमार ने बताया है कि 2022 तक एक लाख 75 हजार मेगावाट की उत्पादन क्षमता का राष्टीय लक्ष्य हासिल करने में कोई समस्या नहीं है। देश में एक लाख 50 हजार मेगावाट क्षमता से अधिक की अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता या तो स्थापित की जा चुकी है या उसको लेकर प्रक्रिया चल रही है। अब केवल 25 हजार मेगावाट की क्षमता की नीलामी की कमी है। यह काम भी 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कुल एक लाख 75 हजार मेगावाट में से 82 हजार 530 मेगावाट उत्पादन क्षमता स्थापित की जा चुकी है और 31 हजार 150 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का निर्माण चल रहा है और इसके साथ ही 39 हजार मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं नीलामी के विभिन्न चरणों में है, जो कि अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। *(न.नु., 12.10.19)*

किसानों की बिजली के नहीं बढ़ेंगे दाम

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किसानों के लिए अगले पांच वर्ष तक कृषि कनेक्शनों पर बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। सरकार की पहली वर्षगांठ पर जयपुर में आयोजित किसान सम्मेलन में यह घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली के बढ़े हुए दामों का भार किसानों को नहीं उठाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार 12 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है।

उन्होंने कहा कि पांच साल तक कृषि कनेक्शनों पर बिजली दरों में इजाफा नहीं करने से सरकार पर 2300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा जिसे भी सरकार वहन करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक हजार करोड़ रुपए से 'किसान कल्याण कोष' का भी शुभारंभ किया। *(दै.भा. एवं दै.न., 18.12.19)*

अधर में अटकी स्मार्ट मीटर योजना

विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए विद्युत विभाग ने योजना बनाई, लेकिन अब तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। बिजली चोरी रोकने के साथ-साथ मीटर रीडर का इंतजार खत्म करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। पिछली सरकार में इस पर तेजी से काम शुरू हुआ था, लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद टेंडर को लेकर बड़ा सवाल उठा और जयपुर डिस्कॉम का मामला सरकार के पास चला गया।

जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम में स्मार्ट मीटर लगाने का काम बड़े स्तर पर होना था। जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम में निविदा प्रक्रिया तो पूरी हो गई लेकिन मीटर लगाने का काम अटका पड़ा है। *(रा.प., 30.12.19)*

नहीं रुक रही विद्युत चोरी व छीजत

राज्य में बिजली दर बढ़ोतरी को लेकर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में सुनवाई शुरू होते ही आपत्तिकर्ताओं ने डिस्कॉम के बिजली दर बढ़ोतरी प्रस्ताव पर सवाल दागने शुरू कर दिए।

आपत्तिकर्ताओं का दो टूक तर्क था कि जो लोग बिजली चोरी नहीं कर रहे और समय पर बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं, उन पर बिजली चोरी और छीजत का बोझ डाला जा रहा है। इसे अब जनता बर्दास्त नहीं करेगी। उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन कर दाम बढ़ाने के प्रस्ताव का जम कर विरोध करते हुए नाराजगी जताई। *(रा.प., 21.11.19)*

प्रदेश में आएगी सोलर-विंड ऊर्जा नीति

देश में सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 2022 तक 100 गीगावाट (जीडब्ल्यू) रखा गया है। इसमें एक चौथाई हिस्सा हमारे प्रदेश राजस्थान का होगा। इसके लिए पांच साल बाद नई सोलर व विंड ऊर्जा नीति लागू की जा रही है। इसके ड्राफ्ट को कुछ दिन पहले जनता के सामने रखा गया और आपत्तियां ली गई। इस नीति में दिए गए लक्ष्य अर्जित होते हैं तो राजस्थान देश में ग्रीन एनर्जी में सिरमौर बन जाएगा।

राज्य सरकार ने अपने बजट में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की कई घोषणाएं की है। इस नीति के तहत प्रदेश में 50 गीगावाट ग्लोबल सोलर हब बनाने, 100 गीगावाट क्षमता के संपूर्ण भारत के लक्ष्य में 25 प्रतिशत की भागीदारी निभाने और 2 हजार मेगावाट के विंड एनर्जी प्लांट लगाने के लक्ष्य रखे गए हैं। *(रा.प., 04.10.19)*

सेंट्रल ग्रिड तक पहुंचेगी ग्रीन एनर्जी

पश्चिमी राजस्थान में बनने वाली ग्रीन एनर्जी को सेंट्रल ग्रिड तक पहुंचाने के लिए पहले गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) तकनीक पर आधारित 765 केवी जीएसएस की कवायद शुरू हो गई है। जोधपुर के समीप कांकाणी में बने 400 केवी जीएसएस को ही अपडेट कर इसे पूरा किया जाएगा। पिछले कुछ समय से ग्रीन एनर्जी का लोड बढ़ने से इसकी बड़ी मांग थी।

अब नई सौर ऊर्जा नीति में प्रदेश में वर्तमान में बनने वाली ग्रीन एनर्जी को अगले पांच सालों में छह गुना तक बढ़ाने की योजना बनाई गई है। ऐसे में जीएसएस और ग्रीन कॉरिडोर काफी महत्वपूर्ण है। पहली बार 765 केवी जीएसएस में गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) तकनीक का उपयोग किया जाएगा। *(रा.प., 22.12.19)*

डिस्कॉम पर बढ़ता जा रहा बकाया

बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बिजली पैदा करने वाली कंपनियों का कुल बकाया इस साल सितंबर में 37 फीसदी बढ़कर 69,558 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यह पिछले साल सितंबर में 50,583 करोड़ रुपए था। यह बताता है कि यह क्षेत्र दबाव के दौर से गुजर रहा है। बिजली वितरण कंपनियां समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पा रही। वेब पोर्टल 'प्राप्ति' के आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है।

इस पोर्टल को मई, 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उत्पादों और विद्युत वितरण कंपनियों के बीच बिजली खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना था। *(दै.भा., 04.11.19)*

पेयजल की पुरानी लाइनें बदहाल

जयपुर की चारदीवारी में पेयजल लाइनें टूटने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाइनें इतनी बदहाल है कि पानी के प्रेशर तक को नहीं झेल पा रही। शहर में आए दिन लाखों लीटर पानी फिजूल बह जाता है। सालों से ऐसी बदहाल लाइनें बदलने के लिए प्रोजेक्ट कागजों में सहेजकर छोड़ रखे हैं। प्रदेश सरकार ऐसे अमृत को बचाने के लिए भी केंद्र सरकार की तरफ मुंह ताक रही है।

चार दिवारी का चिन्हित इलाका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एरिया बेस्ड डवलपमेंट में शामिल है। इसके तहत 50 से 60 करोड़ रुपए पेयजल लाइन बदलने में खर्च होना है। कुछ जगह लाइनें बदली भी गई है लेकिन काम की गति काफी धीमी है। *(रा.प., 10.10.19)*

सक्रिय जल भंडारण क्षमता कितनी?

जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में बताया कि देश में सक्रिय जल भंडारण क्षमता 257.812 अरब घन मीटर है। अनुमानित 3880 अरब घन मीटर वर्षा जल हर वर्ष प्राप्त होता है। इसमें से वाष्पीकरण के बाद 1999.20 अरब घन मीटर जल प्राकृतिक रूप से बचता है। कुल 690 अरब घन मीटर जल भूतल पर रहता है। 432 अरब घन मीटर जल भू-गर्भ में चला जाता है।

उन्होंने कहा कि नीति आयोग की कंपोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडैक्स रिपोर्ट भूजल के पुनर्भरण और उसके निष्कासन के अनुमानों पर आधारित है। इसमें गहरे भूजल स्तर को ध्यान में नहीं रखा गया है। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न अभियानों को जागरूकता के माध्यम से सफल बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

(दै.भा., 10.12.19)

अटका पड़ा है नदियां जोड़ने का काम

राजस्थान में जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए नदियों को जोड़ने की 4 परियोजनाएं पिछले कई सालों से केंद्र में अटकी पड़ी है। इसे लेकर लोकसभा व राज्यसभा में सांसदों ने जल संकट का मामला उठाया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार नदियों को जोड़ने पर विचार कर रही है, लेकिन यह राज्यों का विषय है। इसका मुख्य कारण नदियों के पानी को लेकर अंतरराज्यीय विवाद है।

उन्होंने कहा कि संबंधित राज्यों को आपस में बात कर सहमति बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। इससे आने वाले समय में हम जल संकट से निकल सकेंगे। *(रा.प., 22.11.19)*

जल स्वावलंबन योजना से बढ़ा जलस्तर

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में राजस्थान की पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इसके चलते प्रदेश में प्रतिवर्ष भूमिगत जलस्तर पांच फीट बढ़ रहा है। अन्य राज्य सरकारों को भी इस योजना का अनुसरण करना चाहिए।

उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केवीपीएस राव के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि जल संबंधित केंद्रीय योजनाओं में देरी अंतरराज्यीय विवादों के चलते हो रही है। वहीं भाजपा सांसद करोड़ीलाल मीणा ने कहा कि राजस्थान नहर परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इससे प्रदेश के 113 जिले लाभान्वित होंगे। *(रा.प., 11.12.19)*

जल जीवन मिशनः घरों में नल से पानी

जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 428 करोड़ रुपए मुहैया करवाए गए हैं। केंद्र की हिस्सा राशि के साथ ही राज्य को भी अपने हिस्से के 428 करोड़ रुपए मिशन के तहत खर्च करने होंगे। दरअसल, प्रदेश के केवल 12 प्रतिशत घरों में ही सरकारी नल से लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जा रहा है।

ऐसे में हर घर को नल से पानी मुहैया करवाने के लिए राज्य की ओर से डेटाबेस रिपोर्ट तैयार की गई है। मिशन के तहत प्रदेश के जलदाय विभाग ने 23 प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। इन प्रोजेक्टों में करीब दो हजार करोड़ रुपए खर्च कर करीब छह लाख घरों को घरेलू पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। इनसे करीब 11 हजार गांव-ढाणियों को फायदा मिलेगा। *(दै.न., 05.10.19 एवं दै.भा., 28.11.19)*

नहीं बदले खराब और बंद मीटर

प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा परिवारों को पेयजल शुल्क माफी का फायदा नहीं मिल पा रहा। इन घरों में पेयजल कनेक्शनों पर मीटर नहीं लगे हुए हैं या फिर बंद व खराब पड़े हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की घोषणा का नौ महीने बाद भी फायदा नहीं मिल रहा है।

इंजीनियरों की लापरवाही से उपभोक्ता को औसत पेयजल उपभोग के आधार पर हर महीने 250 से 500 रुपए के बिल भरने पड़ रहे हैं। जबकि इनका पेयजल उपभोग 15 हजार लीटर मासिक से कम है। मुख्यमंत्री ने 8 मार्च 2019 को महीने में 15 हजार लीटर पानी का उपभोग करने वाले परिवारों का पेयजल शुल्क माफ करने की घोषणा की थी। *(दै.भा., 27.12.19)*

अटल भूजल योजना शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेई की 95वीं जयंती के मौके पर अटल भूजल योजना शुरू की है। देश के सात राज्यों मे शुरू होने वाली 6000 करोड़ रुपए की इस योजना के जरिए भूजल का प्रबंधन किया जाएगा।

योजना के प्रथम चरण में राजस्थान और मध्यप्रदेश को भी शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत पैसा सीधे पंचायत जल समिति के खाते में ट्रांसफर होगा। योजना के तहत हर घर तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा। यह योजना जल संकट प्रभावित उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में लागू होगी। इन राज्यों का चयन भूजल की कमी, प्रदूषण और अन्य मानकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। *(रा.प., 26.12.19)*

योजना में वर्ल्ड बैंक भी शामिल

योजना को वर्ल्ड बैंक से मंजूरी मिली है। योजना में 50 फीसदी हिस्सेदारी भारत सरकार की होगी, जबकि आधा हिस्सा वर्ल्ड बैंक की ओर से खर्च किया जाएगा।

पर्याप्त आहार लें तो स्वस्थ रहेंगे नौनिहाल

देश-प्रदेश के विकास में कुपोषण गंभीर समस्या है। देश में एक तिहाई बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इनमें सात में से एक बच्चा गंभीर कुपोषण से ग्रसित है। गर्भवती माताओं को पर्याप्त आहार लेना चाहिए ताकि नौनिहाल स्वस्थ रहें।

जयपुर के एक निजी कॉलेज में पोषण संस्था की ओर से आयोजित 'मातृ एवं शिशु कुपोषण के विरुद्ध जंग' विषयक सेमिनार में विशेषज्ञों ने यह राय रखी। साथ ही कुपोषण को दूर करने के लिए सुझाव भी दिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पौष्टिक खुराक का सेवन करना चाहिए। राज्य सरकार कुपोषण कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। *(रा.प., 18.11.19)*

महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार एवं उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार महिलाओं के प्रति जघन्य अपराधों के त्वरित अनुसंधान के लिए एक विशेष यूनिट बना रही है, जो जल्द से जल्द तफ्तीश कर पीड़ित को शीघ्र न्याय दिलाना सुनिश्चित करेगी।

गहलोत ने यह घोषणा भारतीय महिला फेडरेशन द्वारा रविन्द्र मंच पर आयोजित 21वें सम्मेलन में मुख्य अतिथी के रूप में संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के स्वावलंबन और सशक्तिकरण से ही समाज विकसित बनता है। ऐसे में जरूरी है कि महिलाएं घूंघट छोड़े। *(दै.भा., 28.12.19)*

बचत को लेकर महिलाएं ज्यादा सतर्क

बचत को लेकर पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कुछ ज्यादा ही सतर्क होती हैं। ऑनलाइन वित्तीय सेवा प्रदाता स्क्रिपबॉक्स द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार करीब 58 फीसदी महिलाएं अपना पैसा मियादी जमा या लोक भविष्य निधि में जमा कराना चाहती हैं अथवा फिर उसे बचत खाते में ही पड़ा रहना देना चाहती है। इसके अलावा 6 प्रतिशत प्रतिभागियों की राय में सोना खरीदना अच्छा होता है।

फेसबुक उपयोगकर्ताओं के बीच इस साल अक्टूबर में किए गए इस सर्वे में 400 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसमें 54 प्रतिशत 80 और 90 के दशक में जन्म लेने वाली महिलाएं हैं। इन महिलाओं में तीन चौथाई महिलाएं बचत का समर्थन करती हैं। इसके विपरीत जो 'मिलेनियल्स' आयु वर्ग की नहीं है वे बच्चों की शिक्षा के लिए कोष बनाने का लक्ष्य लेकर चलती है। *(न.नु., 31.10.19)*

स्कूली शिक्षा में प्रदेश दूसरे स्थान पर

नीति आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में समग्र प्रदर्शन (ओवरऑल परफॉरमेंस) के मामले में राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया है।

इस श्रेणी में टॉप दो स्थानों पर दक्षिण के राज्य रहे हैं। केरल नंबर एक और कर्नाटक को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। वहीं निचली पायदानों पर छत्तीसगढ़ 13वें और मध्यप्रदेश को 15वां स्थान मिला है। खास बात यह है कि सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। विश्व बैंक भी इस सर्वे में शामिल रहा। मानव विकास मंत्रालय के नेशनल एचीवमेंट सर्वे के नतीजों को भी संदर्भ के तौर पर सूचकांक में लिया गया है। *(रा.प., 01.10.19)*

आर्थिक समानता में पिछड़े हम

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्लूईएफ) की रिपोर्ट के अनुसार महिला-पुरुषों के बीच आर्थिक समानता में भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। ताजा सूचकांक में हम चार पायदान फिसलकर 112वें स्थान पर आ गए हैं। पिछले साल भारत 108वें स्थान पर था।

महिला-पुरुषों के बीच आर्थिक समानता में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश हमसे कहीं बेहतर स्थिति में हैं। रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में आइसलैंड पहले पायदान पर है, जबकि नार्वे और फिनलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर है। भारत इस मामले में पाक को छोड़कर अन्य पड़ोसी देशों से बहुत पीछे है। ग्लोबल रैंकिग चीन 106वें, श्रीलंका 102वें और बांग्लादेश 50वें स्थान पर रहा। *(रा.प., 18.12.19)*

बालिका शिक्षा के लिए लोन पर छूट

प्रदेश में सहकारी बैंक अब हाउसिंग लोन व बालिका शिक्षा के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए लोन प्रोसेसिंग फीस भी नहीं ली जाएगी। बालिका शिक्षा के लिए पहली बार ब्याज दर पर 0.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह निर्णय बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

यह जानकारी सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव नरेश पाल गंगवार ने देते हुए बताया कि निजी बैंकों की तुलना में सहकारी बैंकों द्वारा कम ब्याज दर 8.20 प्रतिशत फ्लोटिंग पर उपलब्ध कराया जाएगा। *(दै.भा., 28.11.129)*

ऋण लेकर महिलाएं खोल सकती हैं उद्योग

प्रदेश की महिलाओं को उद्योग या व्यापार को बढ़ावा देने और नया उद्योग खोलने के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद करेगी। राज्य सरकार की इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में व्यक्तिगत महिला आवेदकों को 50 लाख रुपए तक और महिला स्वयं सहायता समूहों को एक करोड़ रुपए तक ऋण उपलब्ध कराएगी।

यह योजना महिला अधिकारिता निदेशालय के माध्यम से संचालित है। योजना के तहत बैंकों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा और व्यापार आधारित उद्योगों के लिए ऋण दिया जाता है। योजना में नए स्थापित उद्योगों के साथ-साथ स्थापित उद्योगों का विस्तार भी किया जा सकता है। स्वीकृत ऋण राशि पर 25 प्रतिशत लोन अनुदान दिया जाएगा। एससी/एसटी, विधवा परित्यक्ता, हिंसा से पीड़ित तथा दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं का ऋण अनुदान 30 प्रतिशत होगा। *(दै.न., 31-.12.19)*

सड़क सुरक्षा

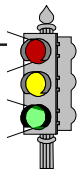

नया मोटर व्हीकल एक्ट

प्रदेश में तय नहीं क्या करेंगे और क्या नहीं?

केन्द्र का नया संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट विवादों के बीच देश में लागू हो चुका है। कुछ राज्यों में भारी-भरकम जुर्माने को आधारहीन मानते हुए विरोध जताया है। राजस्थान में सरकार ने इसमें संशोधन कर जुर्माना कम करने की बात तो कही, मगर एक महीने बाद भी एक्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। पूरा मामला समीक्षा और सियासी पेंच में ही अटका पड़ा है। खुद परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास के पास भी इसका जवाब नहीं है।

उन्होंने कहा कि देश में एक दो जगह ही नया एक्ट लागू हुआ है। हम देख रहे हैं कि देश में एक्ट का विरोध हो रहा है। हम चाहते हैं कि जनहित को ध्यान में रखकर ही इसे लागू करें। सरकार एक्ट को जल्दीबाजी में लागू नहीं करना चाहती। केंद्रीय परिवहन मंत्री अपने ही राज्य में इसे लागू नहीं करा पाए। गुजरात और महाराष्ट्र भी इसे नकार चुके हैं। *(रा.प., 01.10.19)*

प्रदेश में रोजाना 28 लोग बन रहे काल का ग्रास

राजस्थान में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन 28 लोग काल के ग्रास बन रहे हैं। इसमें सर्वाधिक मौत बाइक सवार युवाओं की हो रही है। ओवरलोड वाहन व नशे में वाहन चलाना भी दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनकर सामने आया है। सर्वाधिक दुर्घटनाएं जयपुर में ही हो रही है। उसके बाद अलवर दूसरे व उदयपुर तीसरे स्थान पर है।

परिवहन मुख्यालय की ओर से किए गए सर्वे में राजस्थान की सड़कों पर प्रतिदिन 61 दुर्घटनाओं में 28 लोगों की जान जा रही है। पूरे साल यह मृतकों का आंकड़ा 10 हजार के पार पहुंच रहा है। दुर्घटना में मरने वालों में सर्वाधिक 81 प्रतिशत मौतें 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों की हो रही है।

(रा.प., 17.12.19)

पर्यावरण

देश का वनक्षेत्र बढ़ा, कार्बन सोखने की क्षमता भी बढ़ी

जलवायु परिवर्तन को लेकर यह खबर सचमुच खुश कर देने वाली है। बीते दो वर्षों में देश के वनक्षेत्र में 5188 वर्ग किमी की बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि इसमें 1120 वर्ग किमी घना जंगल है। इसके साथ ही देश के भौगोलिक क्षेत्र में वनक्षेत्र का हिस्सा बढ़कर करीब 25 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2017 में 266 वर्ग किमी जंगल बढ़े थे। इस साल जिन राज्यों में सबसे अधिक वनक्षेत्र बढ़ा है, उनमें कर्नाटक, केरल, आंध्रप्रदेश, जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश शामिल है। राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र में भी वनों की संख्या बढ़ी है। पूर्वोत्तर में असम और त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों में वनक्षेत्र कम हुए हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट-2019 में यह बात सामने आई है।

सर्वे रिपोर्ट में वनक्षेत्र में हुई बढ़ोतरी के हिसाब से कार्बन स्टॉक के बारे में भी अनुमान लगाया गया है। हमारे जंगल सालाना 21.3 प्रतिशत अधिक कार्बन सोख पा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर 2016 में हुए पेरिस समझौते के तहत भारत में 2030 तक 35 प्रतिशत कार्बन सोखने का लक्ष्य रखा गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दुनिया में कुछ ही देश ऐसे है जिनका फॉरेस्ट कवर लगातार बढ़ रहा है और इनमें भारत अग्रणी है। *(दै.भा., 31.12.19)*

वित्तीय सेवाएं

पांच वर्षों में सात गुना बढ़ गए बैंक घोटाले

आर्थिक अपराधों का सर्वाधिक दुष्प्रभाव देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत में बैंकों में वर्ष 2018-19 के दौरान 71 हजार 543 करोड़ रुपए के घोटाले हुए जबकि 2017-18 में 41 हजार 168 घोटाले सामने आए थे। आंकड़े बताते है कि वर्ष 2013-14 के दौरान 10 हजार 170 करोड़ रुपए के घोटाले दर्ज किए गए थे। इस तरह 2018-19 के दौरान घोटालों की रकम वर्ष 2013-14 के मुकाबले पांच वर्षों में सात गुना अधिक हो गई। कुल घोटालों में रकम के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत व घोटालों के आधार पर हिस्सेदारी 55 प्रतिशत रही है। *(रा.प., 17.12.19)*

जन स्वास्थ्य

आयुष्मान योजना में बीमा सुरक्षा अब पांच लाख

प्रदेश में एक सितम्बर से नए रूप से शुरू की गई आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में अब पात्र परिवारों को भी 5 लाख रुपए तक की बीमा सुरक्षा मिलेगी। अब तक अधिकतम सीमा तीन लाख रुपए थी।

चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना देशभर में मिसाल बनेगी। हमने आयुष्मान के साथ भामाशाह बीमा के पात्रधारियों को भी जोड़ लिया है। नई योजना से 1.10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा।

चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र परिवार और सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना डाटा 2011 के तहत चिन्हित परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत अन्य बीमारियों के लिए 50 हजार रुपए और गंभीर बीमारियों के लिए पांच लाख तक की बीमा सुरक्षा मिलेगी। *(रा.प., 03.12.19)*

सेहत से खिलवाड़ तो जिम्मेदार भरेगा जुर्माना

प्रदेश में लाए जाने वाले राइट टू हेल्थ कानून में आमजन की सेहत के प्रति गंभीरता नहीं बरतने वाले महकमें और जिम्मेदार सरकारी एजेंसियां भी दायरे में आएंगी। इसमें आमजन 'रहे हमेशा स्वस्थ' की नीति पर काम किया जा रहा है। प्रदूषण फैलाने सहित मच्छरों को पनपने और उनके बढ़ने को रोकने में नाकाम विभागों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

मॉनिटरिंग और नियंत्रण में फेल रहने पर ऐसे विभागों पर कानून में जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया जाएगा। इसी प्रकार स्वच्छ जल की आपूर्ति, ड्रेनेज व सीवरेज सिस्टम, चिकित्सा, स्थानीय निकाय, परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण मंडल को भी जिम्मेदार बनाया जाएगा। *(रा.प., 05.11.19)*

उपभोक्ता फैसले

ब्लड बैंक को भारी पड़ा संक्रमित ब्लड देना

जयपुर में होली दरवाजा चौमूं निवासी सीताराम सैनी ने मुरलीपुरा स्थित लाइफ केयर ब्लड बैंक के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग की बैंच-2 में परिवाद दर्ज कराया। दर्ज परिवाद के अनुसार उनका 25 साल का पुत्र राहुल जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय चौमूं में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत था। तबीयत खराब होने पर 7 जुलाई 2015 को उसे एमजेएफ अस्पताल चौमूं में दिखाया गया। डॉक्टरों ने उसे पाइल्स से पीड़ित बताया और 10 जुलाई को तीन यूनिट ब्लड चढ़ाने को कहा। मुरलीपुरा स्थित लाइफ केयर ब्लड बैंक से खून मंगाया गया। अभी 50 एमएल ही ब्लड चढ़ा था कि राहुल की तबियत बिगड़ गई। ब्लड चढ़ाना रोक दिया गया। उसे जयपुर रेफर किया गया। लेकिन संक्रमित ब्लड से राहुल की मौत हो गई।

राज्य आयोग ने लाइफ केयर ब्लड बैंक को संक्रमित ब्लड देने का दोषी माना और आदेश दिए कि ब्लड बैंक सीताराम सैनी को 25 लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति अदा करें। साथ ही आयोग ने कहा कि ब्लड बैंक और एमजेएफ अस्पताल दोनों हर्जाने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन, परिवादी ने अस्पताल को पक्षकार नहीं बनाया ऐसे में ब्लड बैंक 25 लाख रुपए देने के लिए जिम्मेदार है। यदि सैनी ने दूषित रक्त चढ़ाने वाले अस्पताल को भी पक्षकार बनाया होता, तो सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों के अनुसार युवक के परिजनों को 50 लाख रुपए मिलते। *(दै.भा., 05.10.19)*

डिग्री यूनानी, इलाज किया एलोपैथी से अब देना होगा हर्जाना

जिला उपभोक्ता मंच जयपुर (तृतीय) में हीरालाल ने रामगढ़ मोड़ स्थित जेडबीएम हॉस्पिटल व डॉ.अहसामुद्दीन के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में उन्होंने बताया कि 2005 में उनकी पत्नी की तबियत खराब हुई तो उक्त हॉस्पिटल में डॉ. अहसामुद्दीन को दिखाया तो गोलियां, इंजेक्शन दिए गए व ग्लूकोज चढ़ाकर रात भर भर्ती रखा। जब तबियत ज्यादा खराब हुई तो अन्य चिकित्सक को दिखाने को कहा और इलाज के कागजात भी नहीं दिए। उसी समय उन्होंने पत्नी को एसएमएस में भर्ती करवाया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अनुसंधान के दौरान मृतका की एफएसएल रिपोर्ट में जहरीले अवयव पाए गए। पुलिस ने यह भी पाया कि डॉ. अहसामुद्दीन यूनानी डिग्री (बीयूएमएस) धारक चिकित्सक है और वह पॉइजन के केस में एलोपैथी ईलाज करने के लिए अधिकृत नहीं है।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने जेडबीएम हॉस्पिटल व डॉ.अहसामुद्दीन को अनुचित व्यापार प्रथा का दोषी माना और 4 लाख 25 हजार रुपए का हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है। मंच ने फैसले में कहा कि अगर डॉ.अहसामुद्दीन परिवादी की पत्नी का सामान्य उपचार कर उसे तत्काल रेफर कर देता तो उसकी जान बच सकती थी। यूनानी चिकित्सक होते हुए पॉइजन के केस में उसने एलोपैथी पद्धति से ईलाज किया जो अनुचित व्यापार प्रथा व सेवादोष की श्रेणी में है। *(दै.भा., 07.12.19)*

अब भारी पड़ेगा किसानों को नकली बीज बेचना

केंद्र सरकार ने मौजूदा बीज अधिनियम 1966 को बदल कर नया बीज कानून बनाने के मकसद से बीज विधेयक 2019 का मसौदा तैयार किया है। माना जा रहा है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ही इसे पेश कर सकती है। इस विधेयक का मकसद किसानों को बेचे जाने वाले बीज की गुणवत्ता का विनियमन करना और अच्छी गुणवत्ता के बीज का आयात-निर्यात करने व देश में गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन और आपूर्ति को सुगम बनाना है।

विधेयक के मसौदे के अध्याय-8 में अपराध एवं सजा शीर्षक के तहत शामिल प्रावधानों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी बीज के आनुवांशिक शुद्धता मानक के संबंध में गलत जानकारी देता है या गलत ब्रांड बताता है अथवा किसी नकली बीज या नकली ट्रांसजेनिक वेरायटी के बीज की आपूर्ति करता है या बिना पंजीकृत कोई बीज बेचता है तो उसे एक साल की जेल की सजा या पांच लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

विधेयक में बगैर पंजीयन प्रमाण पत्र के किसी भी प्रकार का बीज आयात- निर्यात करने, भंडारण करने व बेचने या बीज प्रमाणन एजेंसी, बीज गुणवत्ता जांच अधिकारी या बीज विश्लेषक के कार्य में बाधा डालता है, के बारे में कानूनी रूप से दण्डित करने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। *(न.नु., 16.11.19, 05.12.19)*

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259
फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैराबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)